M/s. FTR Holdings SA, Switzerland which are under consideration of Foreign Investment Promotion Board (FIPB).

Autonomy of GIC

2244. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have granted more autonomy and delegation of power to the General Insurance Corporation; and

(b) if so, what are the details of the additional autonomy and delegation of power granted to GIC?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M. R. JANARTHANAN): (a) and (b) Yes, Sir. Number of powers have been delegated to General Insurance Industry to give them greater autonomy and to ensure that they are Board run. A list of powers delegated to GIC and its four subsidiaries in the recent past is given in the statement below.

Statement

The following are the powers which have been delegated to the GIC to make them Board-run and more autonomous:—

(a) Permission has been given to do non-consortium and unapproved investments without prior approval of the Central Government.

(b) The GIC Board has already been broad-based. It has been decided to broad base the Boards of the subsidiaries of GIC through induction of professionals on their Boards.

(c) Tariff Advisory Committee (TAC) has been reconstituted with Chairman, IRA as its Chairman. Earlier, Chairman, GIC was the Chairman.

(d) Most of the powers of 'Controller of Insurance' have been restored to the Controller which were earlier kept in abeyance in the wake of nationalization of the general insurance industry.

(e) As regards the power to open and close offices of GIC and the subsidiaries, it has been decided that GIC and the subsidiaries may exercise this power subject to their adhering to the statutory limit of manegement expenses as laid down by the Controller of Insurance/ Insurance Regulatory Authority except in specific notified areas like Jammu and Kashmir, North Eastern States etc.

ऋणों की वसूली न किए जाने संबंधी लम्बित विवाद

2245. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में बैंकों व अन्य सरकारी तथा अर्धसरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण का वापस भुगतान न होने के कारण बड़ी संख्या में विवाद अधिकरणों के यहां विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि विवादों को निपटाने के लिए अधिकरणों (ट्रिब्यूनलों) की मौजूदा व्यवस्था अपर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) दिसम्बर, 1998 तक कुल विवादों की संख्या क्या थी तथा इन विवादों में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी और ट्रिब्यूनलों की कितनी शाखाओं में ये विवाद विचाराधीन थे?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन): (क) से (घ) इस समय, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के अंतर्गत देश में स्थापित किए गए नौ ऋण वसूली अधिकरण तथा एक ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण कार्यरत हैं। ऋण वसूली अधिकरणों ने परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं तथा सरकार ने देश में पांच ऋण वसूली अधिकरण तथा चार ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण और स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऋण वसूली अधिकरणों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.1998 तक नौ अधिकरणों में 24539 मामलें दर्ज किए गए थे जिनमें 25614.22 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त थी।